



Neutral Citation No. - 2026:AHC:175505

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29311 वर्ष 2026

बिट्टन @ किरण देवी

.....आवेदिका

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदिका के अधिवक्ता

: हरे राम पांडेय, शशांक पांडेय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए., ललित कुमार श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक पांडेय, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित कुमार श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राकेश कुमार मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 60 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 85, 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना भरतकूप, जिला चित्रकूट में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका मृतका की सास है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आवेदिका

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को केवल मृतका की सास होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है कि उसने मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदिका को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह दर्शाने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा एक महिला होने के नाते वह बी.एन.एन.एस. की धारा 480(1) के दृष्टिगत जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। आवेदिका दिनांक 16.06.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगी।

4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदिका एक **महिला** है और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता (सास) को दृष्टिगत रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन**, प्रकाशित है, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अधिदेश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, प्रकाशित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 के मामले में निर्धारित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदिका-बिट्टन @ किरण देवी, जो उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित है, को व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदिका मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

ii. आवेदिका बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगी।

iii. आवेदिका जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगी।

iv. आवेदिका निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगी।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. आवेदिका एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण को बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. आवेदिका तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर, संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित किए जाने पर, इस शपथ के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदिका की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को भेजे।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि शीर्ष न्यायालय के **पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सूओ मोटू रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, दिनांक 31.01.2023** को निर्णीत, **(2024) 10 एससीसी 685** के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में तथा **पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं एक अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 वर्ष 2025, दिनांक 29.05.2026** को निर्णीत, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति **चित्रकूट जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल पर आवेदिका को तथा ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को 24 घंटे के भीतर भेजी जाए।

19 अगस्त, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”